

Shortage of Paper for Books and Note Books

1048. SHRI T. R. SHAMANNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is acute shortage of paper at reasonable cost to print books and note-books for the use of students; and

(b) if so, steps taken by Government to step up production of paper or import the required paper and supply paper for the above needs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA):

(a) and (b) There is no overall shortage of paper although production of some mills has been affected from time to time due to power shortage, industrial unrest and other factors. Government have arranged for the import of paper to meet the requirements of printers, publishers and other consumers. So far as the educational sector is concerned, white printing paper is being supplied at a concessional price of Rs. 3000 per tonne for publication of text books and manufacture of exercise note books.

"Indians Go Back" slogans in Assam

1049. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that "Indians Go Back" slogans have appeared in Assam;

(b) whether Government have tried to trace the source of such anti-national propaganda; and

(c) if so, the details of the findings of an enquiry, if already made in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA):

(a) to (c). According to information

received from State Government, anonymous posters and wall-writing regarding the slogan referred to have appeared at some places in the State. Efforts made so far have not established the source. The matter is under investigation.

राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में खातेदारी भूमि के अधिग्रहण के लिये मुद्रावजा

1050. श्री विरधी चन्व सेन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों के उन सीमावर्ती क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहाँ सैनिक मकानों के निर्माण के लिए खातेदारी भूमि/ गैर खातेदारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा उक्त ग्रहण कब किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान के राजस्व विभाग द्वारा बार बार ध्यान दिलाये जाने के बावजूद भी रक्षा विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है, और

(ग) रक्षा विभाग द्वारा वहाँ से निकाले गए भू-स्वामियों को सही सही किस तारीख तक मुद्रावजा प्रदा कर दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) . बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में निम्न प्रकार से रक्षा आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए लगभग 328 एकड़ गैर-सरकारी भूमि अधिग्रहीत की गई है और लगभग 84 एकड़ गैर-सरकारी भूमि अजित की गई है .-

(1) मार्च, 1976 में बाड़मेर जिले के मीठरी खुर्द गाव में 133 20 एकड़ गैर-सरकारी भूमि अधिग्रहीत की गई थी। मुद्रावजे की मात्रा के बारे में उक्त जिले के कलक्टर तथा रक्षा भूमि और छावनी प्राधिकारियों के बीच मतभेद होने के कारण आवर्ती मुद्रावजा प्रदा नहीं किया गया है। मामले के व्यूरे मंत्रालय को प्राप्त हो गए हैं।

वित्त (रक्षा) मंत्रालय के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद उचित मुद्रावजा तय किया गया है और इस सम्बन्ध में भुगतान करने के लिए कलक्टर को आदेश भेजे जा रहे हैं।

(2) सितम्बर, 1978 में जैसलमेर जिले के डबला और दरदारी-का-गांव नामक गांवा में 4.2 एकड़ खातेदारी भूमि

अधिग्रहीत की गई थी। जिले के कलक्टर, जो इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी हैं, ने आवर्ती मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं की है। उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई करें।

- (3) दिसम्बर, 1972 में बाड़मेर में 190.68 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। दिसम्बर, 1979 तक का वार्षिक आवर्ती मुआवजा भुदा किया जा चुका है। इस भूमि को अजित करने के लिए अब मंजूरी मिल गई है।
- (4) सन् 1967 में जैसलमेर में 83.72 एकड़ भूमि अजित की गई थी। 85,972 रु० की राशि मुआवजे के रूप में पहले ही वितरित की जा चुकी है और 13,288 रुपये की बकाया राशि तीन भू-स्वामियों में अभी वितरित की जानी बाकी है। मुआवजे के निर्धारण में कुछ अनियमितताओं की शिकायतों के कारण बकाया राशि का वितरण रोक दिया गया है। राज्य सरकार उन शिकायतों की जाच-पड़ताल कर रही है। माननीय सदस्य के साथ-साथ सरकार को भी इस विलम्ब के लिए चिन्ता है और सरकार ने राज्य सरकार से अलग से अनुरोध किया है कि इन मामले में राज्य सरकार का निर्णय शीघ्र भेजा जाए।

Report of Experts Committee on Installation of Atomic Energy Plants

1051. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU:

SHRI R. P. GAEKWAD:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Experts Committee has submitted its report regarding the installation of Atomic Energy Plants in the country; and

(b) if so, whether the above Committee has recommended a site in Andhra Pradesh for this purpose?

THE PRIME MINISTER (SHRI-MATI INDIRA GANDH): (a) Yes, Sir. The Site Selection Committee appointed by the Government for Selection of suitable sites has sub-

mitted its report on the Northern, Western and Southern Electricity Regions.

(b) The Committee has listed sites, including some in Andhra Pradesh, for consideration for the establishment of an Atomic Power Station.

Setting up of a Cement Project at Basohli Jammu

1052. DR. KARAN SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is a long standing proposal for construction of a cement project in Basohli in the Jammu Region;

(b) whether this is all the more necessary in view of the forthcoming construction of the Thein Dam close by; and

(c) if so, what steps are being taken to ensure that this cement factory at Basohli starts functioning as early as possible?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) to (c). Jammu & Kashmir Minerals Limited were granted a letter of intent on 21-4-1971 for setting up a cement plant with a capacity of 2 lakh tonnes per annum at Basohli. Validity of this letter of intent has since expired. No request for revalidation of this letter of intent has been received in this Ministry. It is, therefore, difficult to indicate any time schedule of completion of the project.

Frustration among Scientists of Atomic Energy Establishment,

1053. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the young scientists working under Atomic Energy establishments in the country are suffering from frustration as they do not have ample